nt>

12.23 hrs.

अन्तरिम बजट (रेल)-2004-2005 *

Title: Presentation of the Interim Railway Budget for the year 2004-2005.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष वर्ा 2003-2004 के संशोधित अनुमान तथा वर्ा 2004-2005 के लिए अनुमानित व्यय ए वं प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ । अगले वित्तीय वर्ा से संबंधित अनुमान पूरे साल के लिए हैं परन्तु इस समय मैं सम्मानित सदन से वर्ा के प्रथम चार माह के लिए आवश्यक अनुमानित व्यय को पूरा करने हेतु 'लेखानुदान' देने का अनुरोध कर रहा हूं । वर्ा के बाकी समय की जरूरतें बाद में अलग से स्वीकृति हेतु प्र स्तुत की जाएंगी ।

मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों का विशे रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में ठोस कदम उठाए गए हैं । उनके दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के फलस्वरूप रेलवे अपनी गतायु परिसम्पत्तियों के नवीकरण तथा बदलाव का अत्यन्त जरूरी कार्यक्रम आरम्भ कर सकी है जिसके लिए सुनिश्चित वित्त पोाण सामान्य राजस्व से पर्याप्त समर्थन प्राप्त 'विशे रेल संरक्षा निधि' द्वारा किया गया है। एक अन्य पहल 'राट्रीय रेल विकास योजना' का शुभारंभ है जो रेल नेटवर्क के संतृप्त खंडों की क्षमता में वृद्धि के लिए बनाई गई है । पिछले वर्ा स्वतंत्रता दिवस पर घोाित 'रेल संरक्षा पर टेक्नोलॉजी मिशन' की स्थापना का उद्देश्य संरक्षा, नियंत्रण तथा डिजाइन टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक बनाना है । उनके निर्देशानुसार रेलवे के योजना परिव्यय के बजटीय समर्थन में पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे कई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिली है । इसके अतिरिक्त, बजटेतर पहल से रेलवे ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का मार्ग भी अपनाया है ।

सुरक्षा

यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संसद के चालू सत्र में ही रेलवे एक्ट तथा आर पी एफ एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं । इन संशोधनों के फलस्वरूप रेल सुरक्षा बल को रेलवे एक्ट के तहत छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में जांच करने व अभियोजन की कार्रवाई करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और इस प्रकार, राजकीय रेल पुलिस (जी.आर.पी) गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों पर ध्यान केन्द्रित कर सकेगी । इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और जी आर पी प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक 15 जनवरी 2004 को रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी । बैठक में सुरक्षा संबंधी वियों पर विस्तार से चर्चा हुई । तदुपरान्त, रेल सुरक्षा बल 1 जुलाई,2004 से यात्री गाड़ियों में मार्गरक्षण तथा यात्री क्षेत्र में सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को कारगर ढंग से निभाने की तैयारी कर रहा है ।

*(Placed in Library, See No. LT 8800/04)

राज्यों के साथ इस प्रकार की सुरक्षा संबंधी समन्वय बैठकों को संस्थागत रूप से प्रत्येक वर्ा की 15 जनवरी को आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है ।

संरक्षा

12 और 13 जुलाई,2003 को नई दिल्ली में 'भारतीय रेल पर संरक्षा' के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इसके बाद क्षेत्रीय रेलों पर भी ऐसी ही कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें संरक्षा के प्रति जागरूकता, भारतीय रेल के सभी स्तर के कर्मियों द्वारा संरक्षा को बेहतर बनाने और इस दिशा में सकारात्मक उपाय करने सहित संरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया गया था ।'संरक्षा संवाद' कही जाने वाली यह एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसमें जमीनी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशनों को शामिल किया गया । इन 'संरक्षा संवादों' से जहां एक ओर कर्मचारियों में जागरूकता की भावना और संरक्षा के प्र ति प्रतिबद्धता बढ़ी वहीं प्रशासन चिह्नित क्षेत्रों में तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा कर्मचारियों का भरोसा और विश्वास जीतने में सफल हुआ है ।

पहली बार भारतीय रेल की एक 'समवेत संरक्षा योजना (2003-2013)' तैयार की गई जिसे 19.8.2003 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है। इस संरक्षा योजना में भारतीय रेल के संरक्षा संबंधी लक्ष्यों का समग्र रूप से उल्लेख किया गया है । सभी क्षेत्रीय रेलें और मंडल संरक्षा योजना को अपनी विस्तृत कार्य योजना के द्वारा लागू कर रहे हैं । भारतीय रेल परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में 2002-2003 के दौरान प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर पर घटित होने वाली 0.44 दुर्घटनाओं को काफी कम करते हुए इस अगले चार वर्ाों में 0.30 के स्तर तक लाने के लिए कटिबद्ध है । यह स्तर विश्व की प्रमुख रेलों के उत्कृटतम संरक्षा मानकों में से एक होगा ।

रेल संरक्षा पर टेक्नोलॉजी मिशन

रेल संरक्षा पर टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोाणा के अनुसरण में कार्रवाई करते हुए र्काण एवं चल स्टॉक, रेलपथ एवं पुल, सिगनल एवं दूरसंचार तथा कोहरे में दृश्यता के उपकरणों के क्षेत्र में चार मिशन कार्यक्रमों को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.),कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से चिह्नित किया गया है । रेल मंत्रालय ने इन चार मिशन कार्यक्रमों के अंतर्गत 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है । यह मिशन रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं उद्योगों का संयुक्त प्रयास होगा।

टक्कर रोधी उपकरण (ए सी डी), जिसका नाम 'रक्षा कवच' रखा गया है, के सफल परीक्षण रेलवे द्वारा किए जा चुके हैं । उत्तर रेलवे,पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दक्षिण रेल वे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे पर 3465 किलोमीटर रेल पथ का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसके अलावा 10000 किलोमीटर सर्वक्षण का कार्य प्र ागति पर है । 20 जनवरी 2004 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर 1736 किलोमीटर लम्बे बड़ी लाइन सेक्शन पर टक्कर रोधी उपकरण लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा यह कार्य दिसम्बर,2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है । भारतीय रेल के बाकी बचे बड़ी लाइन सेक्शनों में ए सी डी को क्रमिक रूप से अगले पांच वर्ाों में लगा दिया जाएगा ।

विशे रेल संरक्षा निधि - वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

विशे रेल संरक्षा निधि (एस आर एस एफ),अक्तूबर 2001 में संरक्षा सबंधी कार्यो को छह वित्तीय वर्ा की समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए सृजित की गई थी । मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि मध्यावधि में की गई समीक्षा के दौरान इस क्षेत्र में प्रगति संतोाजनक पाई गई है । प्रथम वर्ा अर्थात् 2001-2002 में इस निधि के अंतर्गत 1434 करोड़ रूपए के कार्य किए गए । वर्ा 2002-2003 के दौरान, विशे रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत कुल 2,486 करोड़ रूपये के कार्य किए गए, इसमें से 1,350 करोड़ रूपये सामान्य राजस्व से योगदान के रूप में थे तथा बाकी राशि रेलवे द्वारा संरक्षा अधिभार की वसूली व रेलवे के अपने राजस्व की सहायता से आई ।

चालू वर्ा में बजट अनुमानों के अनुसार विशेा रेल संरक्षा निधि के लिए कुल शुद्ध आबंटन 2,311 करोड़ रूपये का था जिमसें 1,600 करोड़ रूपये सामान्य राजस्व से योगदान के रूप में तथा 711 करोड़ रूपये संरक्षा अधिभार से थे। संशोधित अनुमानों में इसमें 40 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है ।

जहां तक वास्तविक प्रगति का सबंध है, एस आर एस एफ के माध्यम से 16500 किलोमीटर के रेलपथ नवीकरण का के लक्ष्य में से लगभग 8500 किलोमीटर रेलपथ नवीकरण का कार्य चालू वर्ा के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है । 2700 पुलों के पुनर्स्थापन संबंधी लक्ष्य में से लगभग 1350 पुलों का कार्य चालू वित्तीय वर्ा के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है । इसी प्रकार 1500 स्टेशनों पर सिगनलिंग संस्थापनाओं के बदलाव के लक्ष्य में से लगभग 444 स्टेशनों पर बदलाव का कार्य चालू वर्ा के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, 5300 ट्रैकसर्किट में से लगभग 1675 ट्रैकसर्किट चालू वर्ा के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ।

राट्रीय रेल विकास योजना

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राट्रीय रेल विकास योजना अगले पांच वर्ाों में रेल नेटवर्क के अति महत्वपूर्ण तथा संतृप्त खंडों की क्षमता में वृद्धि के लिए बनाई गई है तथा इसमें 15,000 करोड़ रूपए का अनुमानित निवेश होगा । इस योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज तथा इसके विकर्णों को सुदृढ़ करने, बंदरगाहों से रेल सम्पर्क बढ़ाने और चार महासेतु के निर्माण संबंधी परियोजनाएं शामिल है । योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यो को हाथ में लिया गया है और इनमें पहले दो क्षेत्रों के अधिकांश कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) को सौंप दिए गए हैं जो कि इन कार्यो को तीव्र गति से पूरा करने के लिए कम्पनी एक्ट के तहत गठित किया गया है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने न सिर्फ रेल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राट्रीय रेल विकास योजना से संबंधित परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्वीकृतियों को सुगम बनाने में योगदान दिया है वरन् इनके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से की है।

2003-2004 के संशेधित अनुमानों में रेल विकास निगम के लिए 500 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है जिसे निगम इन परियोजनाओं पर खर्च करेगा। 2004-2005 के दौरान रेल विकास निगम ने इन कार्यो पर 1,000 करोड़ रूपये खर्च करने की योजना बनाई है जिसमें से 300 करोड़ रूपये बाजार से उठाए जाने की आशा है ।

परियोजनाएं

सभी परियोजानाओं पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा इन्हें समय से पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ा हो रहा है कि जम्मू-उध्मपुर नई लाइन परियोजना का कार्य पूरा होने के करीब है और यह लाइन लक्ष्य से पहले ही 25 मार्च 2004 से यातायात के लिए खोल दी जाएगी ।

अतिरिक्त गाड़िया / सेवाएं

2003-2004 के बजट भााण में घोाित की गई नई गाड़ियों, चालन क्षेत्र के विस्तार वाली सेवाओं, गाड़ियों के फेरों में वृद्धि,मेमू/डेमू (एमईएमयू/ डीईएमयू) सेवाओं में से अधिकांश को प्रारम्भ किया जा चुका है तथा शेा को यथाशीघ्र चलाया जाएगा । इनके अतिरिक्त वर्ा के दौरान 35 अन्य सेवाओं को प्रारम्भ किया गया है जिनमें जन साधारण एक्सप्रेस भी शामिल है।

टिकट बिक्री हेतु नए उपाय

ग्राहकों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (पीआरसी) की सीमाओं का इंटरनेट बुकिंग के द्वारा विस्तार किया गया है । अब आरक्षण टिकट ग्राहकों के घर तक भी पहुंचाये जाने लगे है । अनारक्षित टिकटों के मामले में यात्रियों की परेशानियां बनी हुई थीं । पिछले साल कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू टी एस) की शुरूआत से एक विशेा सफलता हासिल हुई है जिसे यात्रियों ने काफी सराहा है । इस प्रणाली का आगे और विस्तार करने का प्रस्ताव है । इन प्रयासों से भारतीय रेल की समूची टिकट प्रणाली अत्याधुनिक हो गई है ।

आरक्षित टिकट प्रणाली को ई-टिकेटिंग द्वारा एक नया आयाम देने का प्रस्ताव है । कुछ चुनिंदा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों पर एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी जिसके अन्तर्गत यात्रीगण इंटरनेट से आरक्षण करवाकर एक कम्प्यूटर जनित पर्ची के आधार पर गाड़ी में अपना आरक्षित स्थान ग्रहण कर सकेंगे। संचार उपकरणों के प्रसार तथा आम आदमी द्वारा मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग को रेलवे नज़रअदांज नहीं कर सकती है । अब मोबाइल फोन के जरिए इच्छुक व्यक्ति आरक्षण करवा सकेंगे । भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआर सी टी सी) ने तकनीकी क्षमता का विकास किया है जिससे सेल फोन ऑपरेटर अपनी प्रणाली को रेलवे की प्रणाली के साथ एकीकृत कर सकेंगे । यह सुविधा सभी सेल फोन ऑपरेटरों को उपलब्ध रहेगी ।

गैर-व्यस्त काल के दौरान चुनिन्दा गाड़ियों पर प्रयोग के तौर पर घटे हुए किरायों की योजना की लोकप्रियता से उत्साहित होकर राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी के प्रथम व द्वितीय वातानुकूल तथा कुर्सीयान श्रेणियों में बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नियमित प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत ऐसे रेल यात्रियों को उनके द्वारा एक वर्ा की अवधि में की गई यात्राओं के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा । इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक यात्रियों को पंजीकृत किया जाएगा और निर्धारित यात्राएं कर लेने के बाद वे एक मानार्थ यात्रा के हक़दार होंगे ।

एस.एस.एस. के जरिए गाड़ी पुनर्निधारण की सूचना

राजधानी,शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों के 30 मिनट से अधिक विलम्बित प्रस्थान की स्थिति में सूचना इच्छुक यात्रियों को उनके मोबाइन फोन पर एस एम एस के जरिए मिल सकेगी । प्रारम्भ में यह पायलट स्कीम दिल्ली क्षेत्र में प्रस्थान करने वाली ऐसी गाड़ियों के लिए होगी ।

तत्काल स्कीम का विस्तार

इस समय तत्काल आरक्षण स्कीम केवल चुनिन्दा गाड़ियों में और मुख्यतः शयनकाल श्रेणी में उपलब्ध है। कम सूचना पर चलने वाले यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सेवा को सभी गाड़ियों में तथा शयनयान, कुर्सीयान,वातानुकूल तृतीय श्रेणी और वातानुकूल द्वितीय श्रेणी में भी लागू करने का प्रस्ताव है ।

2002-2003 के कार्य निपादन की समीक्षा

मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ढुलाई के लक्ष्य को 510 मिलियन टन से 515 मिलियन टन तक संशोधित करने का निर्णय सर्वथा उचित था क्योंकि रेलवे ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 518.74 मिलियन टन की ढुलाई की और पिछले वर्ा की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यात्री किलोमीटर में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्राप्तियों के व्यय पर'आधिक्य' में बजट से 95 करोड़ रूपए का सुधार हुआ । निपादन में सुधार के फलस्वरूप 92.34 प्रतिशत का बेहतर परिचालनिक अनुपात प्राप्त हुआ । वास्तविक योजना व्यय 11,408 करोड़ रूपये रहा जबकि संशोधित अनुमान 12,315 करोड़ रूपए था ।

संशोधित अनुमान 2003-2004

र्वा 2003-2004 के लिए 540 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । दिसम्बर,2003 तक 407.15 मिलियन टन की ढुलाई कर लेने के बाद, जो कि आनुपातिक लक्ष्य से अधिक है , यह आशा की जाती है कि रेलवे न केवल पूरे साल के लक्ष्य को पा लेगी वरन् इससे ज्यादा ढुलाई करेगी । तदनुसार, लक्ष्य को संशोधित कर 550 मिलियन टन किया जा रहा है । यात्री यातायात ने 2.8 प्रतिशित से अधिक की वृद्धि दर्ज की है ।

सकल यातायात प्राप्तियां

प्राप्तियों का रूझान बजट की आशा के अनुरूप नहीं रहा है । अतः संशोधित अनुमान 890 करोड़ रूपये कम है और सकल यातायात प्राप्तियों को इतनी ही धनराशि से कम करते हुए संशोधित किया जा रहा है । ट्रैफिक सस्पेंस से निपटान के लक्ष्य में परिवर्तन न करते हुए इसे बजट स्तर पर ही बनाए रखा गया है ।

संचालन व्यय

दिसम्बर के अंत तक व्यय में आई बचत के रुख को देखते हुए साधारण संचालन व्यय में 1490 करोड़ रूपय की शुद्ध रूप से कमी आने का अनुमान है । पेंशन निधि में विनियोग 295 करोड़ रूपये से घटा दिया है जो कि अभी तक के वास्तविक व्यय के अनुरूप है । जरूरतों के मद्देनजर मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 262 करोड़ रूपए से बढ़ा दिया गया है । इस प्रकार कुल संचालन व्यय 40,850 करोड़ रूपए से 1,523 करोड़ रूपए घटकर 39,327 करोड़ रूपये रह जाते हैं ।

इन परिवर्तनों तथा शुद्ध विविध प्राप्तियों में मामूली कमी के फलस्वरूप शुद्ध राजस्व 3,533 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में बढ़कर 4,148 करोड़ रूपये होगा ।

बजट अनुमानों के अंतर्गत 2,933 करोड़ रूपये के लाभांश भुगतान का प्रावधान किया गया था जिसे अब संशोधित कर 2,968 करोड़ रूपये किया गया है । संसाधनों की बेहतर उपलब्धता के फलस्वरूप आस्थगित लाभांश दायिता को पूरा करने संबंधी जिस प्रयास को पिछले बजट में शुरू किया गया था, उसे 300 करोड़ रूपये के प्रा वधान के साथ आगे जारी रख जा रहा है । इस प्रकार संशोधित अनुमान में लाभांश भुगतान का प्रावधान बढ़ाकर 3,268 करोड़ रूपए कर दिया गया है ।

इन परिवर्तनों के साथ, प्राप्तियों का व्यय पर'आधिक्य' 880 करोड़ रूपए बनता है जो बजट में 600 करोड़ रूपए अनुमानित था । इसे विकास निधि तथा विशेा रेल संरक्षा निधि में विनियोजित किया जा रहा है ।

2003-2004 के लिए वार्षिक योजना

रेलवे की वार्षिक योजना 2003-2004 में, 12,918 करोड़ रूपयेका कुल परिव्यय रखा गया था । संशोधित अनुमानों में इसे बढ़ाकर 13,918 करोड़ रूपये कर दिया गया है । 1,000 करोड़ रूपये की यह वृद्धि राट्रीय परियोजना उध्मपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन के लिए 500 करोड़ रूपये रूपये के अलग आबंटन, कुछ परियोजनाओं को पूरा करने की गति बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रूपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता तथा आंतरिक संसाधन में 200 करोड़ रूपये के बढ़ाए गए परिव्यय द्वारा हुई है ।

बजट अनुमान 2004-2005

सकल यातायात प्राप्तियां

अब मैं 2004-2005 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा । किरायों तथा मालभाड़ा दरों के वर्तमान स्तर पर र्वा के लिए 44,482 करोड़ रूपए की सकल यातयात प्र ाप्तियां होने का अनुमान है । चालू र्वा के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,877 करोड़ रूपए की यह बढ़ोत्तरी यात्रियों की संख्या में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि तथा 570 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात के अनुमान पर आधारित है जो 2003-2004 के संशोधित लक्ष्य से 20 मिलियन टन अधिक है ।

साधारण संचालन व्यय

साधारण संचालन व्यय,32960 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जो कि चालू र्वा के संशोधित अनुमान से 1,990 करोड़ रूपये से अधिक है ।

पेंशन भोगियों की संख्या में वृद्धि तथा मंहगाई राहत में बढ़ोत्तरी के कारण पेंशन निधि में विनियोग को इस वित्तीय र्वा के संशोधित अनुमानों से 300 करोड़ रूपये बढ़ाकर 6,390 करोड़ रूपये कर दिया गया है । मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग के लिए 1,900 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव है ।

कुल संचालन व्यय 41,250 करोड़ रूपये होने का अनमान है तथा 3,232 करोड़ रूपये की शुद्ध यातायात प्राप्तियां होंगी । शुद्ध विविध प्राप्तियों के रूप में 993 करोड़ रूपये की राशि का अनुमान है और इस प्रकार शुद्ध राजस्व 4,225 करोड़ रूपये होगा ।

वित्तीय परिणाम 2004-2005

2004-2005 के लिए सामान्य राजस्व को देय लाभांश का आकलन अनन्तिम तौर पर 2003-2004 की भांति ही किया गया है और यह 3305 करोड़ रूपये बनता है जिसे पूर्णतया भुगतान करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, आस्थगित लाभांश दायिता हेतु 300 करोड़ रूपये का भुगतान करने का प्रस्ताव है । इस प्रकार, प्राप्तियों का व्यय'आधिक्य' 620 करोड़ रूपये होगा ।

वार्षिक योजना 2004-2005

2004-2005 की वार्षिक योजना फिलहाल 13,425 करोड़ रूपये की रखी गई है । इसमें 4,544 करोड़ रूपये की बजटीय सहायता, 2635 करोड़ रूपये के आंतरिक संसाधन, 2,795 करोड़ रूपये का विशेा रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत परिव्यय तथा रेलवे संरक्षा निधि के अंतर्गत 401 करोड़ रूपये शामिल है । बजेटतर संसाधन 3,050 करोड़ रूपये रखे गए हैं ।

सुदूर क्षेत्र रेल सम्पर्क योजना

रेलवे के पास इस समय नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं महानगरीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत लगभग 43,000 करोड़ रूपये की स्वीकृत परियोजनाओं की कुल 230 से अधिक की संख्या मौजूद है । बढ़ी हुई बजटीय सहायता, राट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत बजटेतर पहल, लागत में

भागीदारी वाले अन्य प्रयासों तथा सामरिक महत्व की कुछ परियोजनाओं के रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोाण के बाजवूद अगले पांच वार्षों के बाद भी लगभग 20,000 करोड़ रूपये की परियोजनाएं बाकी बची रहेंगी । इनमें से कई परियोजनाओं को सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े व सुदूर क्षेत्रों को रेलमार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से मंजूरी मिली थी लेकिन धन के अभाव में परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है जो आमतौर पर असंतोा का कारण बनती है । रेल लाइन को ऐसे क्षेत्रों से जोड़ने से इन इलाकों की सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा तथा निर्माण काल के दौरान एंव बाद में रोजगार के अवसर भी बड़ी मात्रा में सृजित होंगे। इन बातों के मद्देनजर ऐसी सभी परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाने और उन्हें आगामी पांच वार्षों के अन्दर पूरा करने का निर्णय लिया गया है । मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ा है कि लगभग 20,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त निवेश से एक महत्वाकांक्षी 'सुदूर क्षेत्र रेल सम्पर्क योजना' आरम्भ की जा रही है ।

अगर मोटे तौर पर आकलन करें तो सभी परियोजनाओं को पांच वर्ा की समय सीमा में पूरा करने के दौरान निर्माण काल में लगभग तीन लाख लोगों को प्रति वर्ा रोजगार मिलेगा । इन लाइनों को चालू हो जाने के बाद भी सामान्य अनुरक्षण एवं परिचालन के लिए प्रति वर्ा बढ़ने वाली करीब 18000 व्यक्तियों की स्थायी आवश्यकता होगी । इसके अलावा, प्रतिवर्ा लगभग 55000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे ।'सुदूर क्षेत्र रेल सम्पर्क योजना' से देश के दूर दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को बदलने तथा इन क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में काफी मदद मिलेगी ।

*.....(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI(RAIGANJ): Sir, where is the mandate for the Minister of Railways for the Next five years?.....(Interruptions)

SHRI S.JAIPAL REDDY(MIRYAGUDA) : He has the mandate for poll survey, not from the people.. ..(Interruptions)

श्री नीतीश कुमारः चिन्ता मत करिये, वापस यही सरकार आयेगी । इसको आगे बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग आगे की सब योजनाएं बना रहे हैं । **.... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नीतीश कुमार जी, यह भााण में नहीं लिखा है ।

श्री नीतीश कुमारः यहीं नहीं, इससे स्टील,सीमेंट, चल स्टॉक, फिटिंग, पुर्जे, संयंत्र एवं मशीनरी की मांग भी पैदा होगी जिससे सारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नई सेवायें

महोदय, लोकतंत्र में लोक भावना सर्वोपरि होती है । आज यह भावना सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जनता द्वारा सम्पर्क बढ़ाने की आकांक्षा के रूप में दिखती है । इस जनभावना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यरूप में ढालते हुए रेल,सड़क तथा संचार सहित सम्पर्क के सभी माध्यमों का बहुमुखी विकास किया है । वास्तव में उन्होंने सम्पर्क क्रांति का सूत्रपात किया है। रेलवे सदा से सम्पर्क का लोकप्रिय माध्यम रही है। अतः राज्यों का राट्र की राजधानी से द्रुत सम्पर्क स्थापित करने के लिए 'सम्पर्क क्रांति' नाम से गाड़ियों की एक नई श्रृंखला चलाई जाएगी जो एक राज्य विशेा को राट्रीय राजधानी से जोड़ेगी और इसमें राज्य के बाहर नॉन स्टॉप यात्रा, पूरी यात्रा के दौरान पूर्णरूपेण निर्दिट कर्मचारी सेवा और जन उद्घोाणा प्रणाली जैसी मूल्य संवर्धित विशेाताएं उपलब्ध होगी । अपनी तरह की यह अपूर्व सेवा होगी । इस श्रृंखला की पहली गाड़ी कर्नाटक सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस,दिल्ली (निज़ामुद्दीन) तथा बैंगलोर (यशवंतपुर) के बीच इस साल 8 फरवरी से चलाई जा रही है ।

श्री रामदास आठवले(पंढरपुर) - मुम्बई के लिए योजना है या नहीं है ?

श्री नीतीश कुमारः हालांकि शुरूआत में यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलेगी पर 2 अक्तूबर,2004 को बापू के जन्म-दिवस के अवसर पर इसे प्रतिदिन कर दिया जाएगा ।

इस श्रृंखला की अन्य गाड़ियां निम्नानुसार होगी -

i. पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से गुवाहाटी तक
ii. आन्ध्र प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से सिकंदराबाद तक
iii. बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से समस्तीपुर तक
iv. छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से दुर्ग तक
v. गुजरात सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से अहमदाबाद तक
vi. झारखंड सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से रांची तक
vii. केरल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से त्रिवेन्द्रम (कोचुवेलि) तक
viii. महाराट्र सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से मुम्बई (बांद्रा) तक
ix. मध्य प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से जबलपुर तक
x. उड़ीसा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक
xi. राजस्थान सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से जोधपुर तक
xii. तमिलनाडु सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से मदुरै तक
xiii. उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से चित्रकूट तक
xiv. उत्तरांचल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से काठगोदाम तक
xv. पश्चिम बंगाल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से कोलकाता (सियालदह) तक
xvi. गोवा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन)से मंडगांव तक
xvii. उत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से ऊधमपुर तक जो जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जरूरतों के लिए होगी ।

उपसंहार

महोदय, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, संरक्षा और सुदृढ़ बनाने तथा राट्र की इस जीवन-रेखा के प्रति लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई पहल किए गए हैं । रेल कर्मचारियों के सभी स्तरों पर दिखाई गई निठा व कर्त्तव्यपरायणता की सराहना यह सदन करता है । सदन ने रेलवे को आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के एक साधन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने तथा साथ ही वित्तीय रूप से जीवन्त रहने के लिए सदैव समर्थन देने की कृपा की है । मुझे विश्वास है कि रेलवे विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सदैव सक्षम रहेगी ।

महोदय, इसके साथ मैं अंतरिम रेल बजट सदन में संस्तुत करता हूँ ।

12.45 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - (RAILWAYS), 2003-2004